†شری سکندر بخت : - ہم یہ امید کر رہے تھے کہ سرکار کی طرف سے مناسب ری ایکشن آئے گا لیکن کمال کی بات ہے کہ یہاں کوئی ری ایکشن آتے ... "مداخلت" ... کسی قسم کا ری ایکشن ظاہر کرنے کو سرکار تیار نہیں ہے ... "مداخلت" ... صدر صاحبہ - گورنمنٹ کے اس رویہ سے ہمیں سخت اعتراض ہے - ہمیں شکایت ہے کہ ایک غلط چارج شیٹ دائر کرنے کے بعد سرکار اپنی غلطی کو درست کرنے کے لئے تیار نہیں ہے - ... "مداخلت" ... ہم سرکار کے اس رویہ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں اور واک آوٹ کرتے ہیں -

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० अबरार अहमद) : गवर्नमेंट इसके लिए वक्तव्य दे चुकी है। **(व्यवधान)** हर बात का खुलासा कर चुकी है। सारी बात सदन के सामने रख चुकी है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Question No. 141.

*141. [The Questioner (Sri Gopalsinh G. Solanki) was absent. For answer vide Col... infra.]

*142. [The Questioner (Shri Kailash Narain Sarang) was absent. For answer Vide Col. ... infra.]

THE DEPUTY CHAIRMAN. Question No. 143 Mr. Patel.

Tea Auction Centre in Ahmedabad

*143. SHRI AHMED MOHEMADBHAI PATEL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat have decided to open a tea auction centre in Ahmedabad in November, 1993 ;

(b) whether this move was opposed by the Government of Assam on the plea that the proposed Tea auction centre in Ahmedabad would adversely effect the economy of Assam ; and

(c) if so, whether Government have decided to defer the decision ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED: (a) No formal request for a licence to open a tea auction centre by the Gujarat Govt. in Ahmedabad has been received. However it has been brought to the notice of the tea Board by Gujarat Tea Traders Association that State Govt. of Gujarat has proposed to open a tea auction centre in Gujarat.

(b) Yes, Madam.

(c) Under the provisions of Tea (marketing) Control Order, 1984 a licence is required to be obtained from Tea Board for opening of a new tea auction centre. No formal request for opening of auction centre at Ahmedabad has been received by the Tea Board. State Government of Gujarat has been apprised about the statutory provisions in this regard.

श्री अहमद मोहम्मद भाई पटेल : महोदया हमारे देश में जो चाय का इस्तेमाल होता है, उसमें से 25 प्रतिशत गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है और उसे ध्यान में रखते

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

हुए वहां की ट्रेडर्स एसोसिएशन और गुजरात सरकार ने प्रस्ताव किया था कि अहमदाबाद में चाय नीलामी केन्द्र खोला जाए। 18 नवम्बर को यह शुरू होने वाला था कि आसाम की सरकार ने आपत्ति की। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आसाम की सरकार की आपत्ति के मुद्दे क्या हैं और उसको कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक्जामिन किया है या नहीं ?

श्री कमलालुद्दीन अहमद : सर्वप्रथम कानूनी तरीके से इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वैस्ट आनी चाहिए, वह रिक्वैस्ट ही गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। सिर्फ इस इत्तला पर कि गुजरात गवर्नमेंट ऐसा कुछ करना चाहती है, उस पर आसाम गवर्नमेंट ने, आसाम गणपरिषद् ने और वहां के दूसरे ऑर्गनाइजेशंस ने कहा है कि इससे आसाम को नुकसान होगा इस किस्म का रिप्रजेंटेशन उन्होंने दिया है, लेकिन फैक्ट यह है कि गुजरात गवर्नमेंट या किसी ने भी वहां पर टी-ऑक्शन सेंटर खोलने के लिए कानून के तहत कोई फॉर्मल रिक्वैस्ट नहीं की है।

श्री अहमद मोहम्मद भाई पटेल : महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अगर गुजरात की सरकार फॉर्मल रिक्वैस्ट भेजेगी तो मंत्री महोदय सदन को कोई ठोस आश्वासन देंगे कि रिक्वैस्ट आने पर इसकी परमीशन दी जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि आसाम के अलावा और किन-किन जगहों पर ऐसे केन्द्र खोले गए हैं और वहां केन्द्र खोले जाने के बाद आसाम की आर्थिक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं। तीसरा सवाल मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे आर्थिक सुधार की जो उदार निती है, उससे यह हमारी गुजरात सरकार का जो प्रस्ताव या रिक्वैस्ट आएगी वह सुसंगत या अनुकूल है या नहीं और अगर है तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि जैसे ही फॉर्मल रिक्वैस्ट आएगी तुरंत ही गुजरात सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : अभी तो ऑक्शन के 7 सेंटर्स हैं। इनमें से 6 सेंटर्स या तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में हैं या उसके आसपास हैं। एक ही सेंटर नॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट में है और वह अमृतसर में है। अमृतसर के अलावा और जो 6 सेंटर्स हैं, उनमें एक कलकत्ता में है, दूसरा सिलिगुड़ी, तीसरा गोहाटी, चौथा कोचीन, पांचवां कुनूर और छठा कोयम्बटूर में है। अब रहा प्रस्ताव का तो अगर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो टी बोर्ड उसके ऊपर जरूर गौर करेगा। टी-बोर्ड का ऑक्शन सेंटर ओपन करने के बारे में कुछ क्रायटेरिया होता है, उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में होगी। उसके लिए इकॉनोमिक वायबेलिटी देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और फिर उससे बेनेफिट टू द टी सेंटर एंड व कंज्यूमर्स भी देखते हैं। यह मोटे तौर पर इसका क्रायटेरिया है और इस क्रायटेरिया को अगर गुजरात गवर्नमेंट सेटिसफाय करती है तो नेचुरली टी बोर्ड उस पर गौर करेगा।

चौधरी हरि सिंह : महोदया, चाय हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय पेय है और देश के हर कोने में इसकी मांग होती है, लेकिन इसकी जो नीलामी होती है, वह मोस्टली उन स्टेट्स में होती है जहां पर कि चाय पैदा होती है। इससे यह दिक्कत आती है राष्ट्र के सामने और चाय पीने वालों के सामने की अच्छी क्वालिटी की चाय उनको देश के हर कोने में नहीं मिल पाती। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, उन्होंने कुछ क्रायटेरिया दूसरे स्टेट्स में ऑक्शन सेंटर बनाने के बारे में बताए हैं, लेकिन पूरे नहीं बताए हैं कि ऑक्शन सेंटर बनाने के और क्या क्रायटेरिया होंगे ? दूसरे अप्लाय करने के संबंध में क्या प्रोसीजर है, वह भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

उपसभापति : वह प्रोसीजर अगर बहुत लंबा है तो I would not permit on the floor of the House because he cannit read the whole procedure.

श्री कमालुद्दीन अहमद : प्रोसीजर नहीं एप्लीकेशन दें टी बोर्ड को तो टी बोर्ड गौर करता है। रही बात अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी की चाय की, तो वह हर जगह अवेलेबल हो सकती है। दाम पर मुनहसिर है वह। अच्छा दाम अगर देंगे तो अच्छी चाय मिलेगी। अगर कम दाम देंगे तो कम क्वालिटी की चाय मिलेगी।

उपसभापति : आक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : आक्शन तो हर किस्म की चाय का होता है। आक्शन में दार्जिलिंग की चाय भी होती है, आक्शन में आसाम की चाय भी होती है, नीलगिरि की चाय भी होती है... **(व्यवधान)**

उपसभापति : सेंट्रल हाल में सबसे अच्छी चाय मिलती है।

श्री शंकर दयालसिंह : इस चाय की नीलामी के सेंटर के संबंध में क्या इसका व्यवसायिक और आर्थिक पक्ष है, वह मैं बहुत नहीं जानता और न ही इसमें पूछना चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं जैसे हरि सिंह जी ने कहा कि चाय सच में एक राष्ट्रीय पेय है इस सबके बावजूद। गरीब और अमीर सभी उसको व्यवहार में लाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार इसके मूल्य का नियंत्रण रखने हेतु जिससे यह केवल बड़ी तिजारत की ही चीज न रहे, जैसे ब्रुक बांड, लिप्टन तथा ताज आदि की चाय है, वह महंगी चाय है, लेकिन गरीबों को भी सर्वसुलभ हो इसके लिए क्या आप अधिक सेंटर्स हर प्रांत की राजधानी में सरकार के उद्यम से खोलने पर विचार करेंगे ताकि ये नीलामी सेंटर्स खुलें और चाय की कीमत में कमी आ सके और आम जन भी लाभ उठा सकें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : कम कीमत की चाय के लिए लिमिटेड तरीके से पिछले कुछ सालों में यहां कोशिश की गयी थी एन०सी०सी०एफ० की तरफ से। नेशनल कोओपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन की तरफ से कुछ कम कीमत की चाय के पैकेट्स सप्लाई किए गए थे सुपर बाजार वगैरह में, लेकिन पूरे देश के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए यह उस स्टेट्स पर आधारित है। कुछ स्टेट्स में टी को पी०डी०एस० में रख कर सप्लाई कर रहे हैं। बाज स्टेट्स में यह है। लेकिन अब यह उन स्टेट्स पर मुनहसिर है।

SHRI ASHOK MITRA : Madam, over the last four or five years. there have been convulsions in the international tea market on account of the collapse of the Soviet Union and there has been some impact of this on the auction houses operating in the country. There is some allegation that the multi-national corporations are manipulating the activities in the auction centres. Could I, therefore, through you, Madam, kindly request the Minister whether he would be willing to set up a small enquiry committee to review the affairs of all these auction centres?

SHRI KAMALUDDIN AHMED : The Tea Board is there to look after all these things. To my knowledge, they do not have any such complaint with them that such manipulations are being carried on. (*Interruptions*). As you know, tea production was there on a large scale with the foreign planters only earlier. Madam, the auction is done very systematically and it is open. There is so much of transperancy in this. There is no question of doing any *hera-pheri* in this.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA : Some time back, I had written a letter to the Ministry that handles these auction matters that manipulations are going on at the auction centres. The prices are so managed that it becomes very difficult to provide cheaper tea to other centres. In such a situation, Shri Ashok Mitra has rightly drawn the attention of the Minister to the fact that such manipulations are going on—what is wrong in opening more centres if there is a demand? If the demand comes, you can also change the criteria in order to check the manipulations that are going on. So, let there be more competition.

उपसभापति : आप सवाल पूछिए, आप पालिसी पर मत बोलिए ।

श्री चिमनभाई मेहता : वही तो मैं बोल रहा हूं ।

उपसभापति : आप जरा कह दीजिए कि वट इज द प्राब्लम ।

श्री चिमनभाई मेहता : हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गुजरात की चाय के बारे में है । इसकी जानकारी के हिसाब से कह सकता हूं अगर टी-सेंटर वहां खोला जाएगा तो जनता को चाय सस्ते में उपलब्ध होगी और प्रोड्यूसर्ज को ज्यादा फायदा होगा ?

उपसभापति : टी-सेंटर नहीं खोल रहे हैं ।

श्री चिमनभाई मेहता : आप इस बारे में कहिए ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैंने शुरू में ही कहा कि अगर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो टी-बोर्ड उस पर गौर करने के लिए तैयार है और गौर करेगा कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं से सेंटर खोलने की रिक्वेस्ट हो, कहीं से रिक्वेस्ट की गई हो और उस रेक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया गया हो । *(Interruptions)* ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order please. The Minister has answered that there are certain procedures. If the various States applied, they would do it. Let them ask for it.

Next Question.

Decision on the expert committee report on Public Distribution System

*144. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the Experts Committee report for the restructuring of the Public Distribution System;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, by when Government propose to take a final decision on the said report?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A.K. ANTONY): (a) to (c) The report of the Committee of Minister on National Policy on Public distribution System (PDS) has been received by the Government and was considered by the Advisory Council on PDS at its meeting held on 22-9-93. The Advisory Council was unanimous in its opinion that the report would require further consultation with the States. Considering the importance of the matter, the Council resolved that the report may be referred to the National Development Council for their consideration and for evolving acceptable policy guidelines/on PDS. Government will take a decision after getting the recommendation of the National Development Council (NDS).

SHRI M. A. BABY: Madam, from the reply it is obvious that there is some delay taking place in taking a decision at the Government level and there is nothing strange for the present Cabinet taking no decisions or delaying decisions. It has become a hallmark of the present Cabinet led by Shri Narasimha Rao to ensure that decisions are delayed to the extent possible.

Madam, the importance of taking a decision in this matter is very crucial because in a large country like ours a huge segment of population lives below the poverty line. The effective working of the public distribution system is to ensure that at least a subsistence is given to a majority of the poor people in our country. Madam, it is known that the existing public distribution system hardly covers a sizeable section of our population. Except for a State like Kerala, the public distribution system itself is not effective in most parts of our country.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you please put a question? No, you are not putting a question.

SHRI M. A. BABY: I am building my case.